BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any time schedule for the Doordarshan to make payments to the producers of the films selected by the Doordarshan for telecast;

(b) whether it is a fact that there are some middlemen who get such payments released against considerable amount of money;

(c) what is the number of regional feature films which were telecast during the period from 1st January, to 31st October. 1987 with their dates of telecast; and

(d) on which dates the payments for these films have been released?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) No, Sir. But efforts are made to release payments as soon as possible.

(b) The Government is not aware of such cases.

(c) and (d) The information is given in the enclosed statement. [*See* Appendix CXLIV, Annexure No. 91]

Approval of T.V. serials

2098. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the total number of serials approved by the Doordarshan till date;

(b) what is the total number of serials pending for approval with the Doordarshan; and

(c) what steps Government propose to take to expedite the approval of the serials?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) to (c) Doordarshan stopped acceptance of proposals for T.V. serials with effect from 7.5.1986. Till that date, a total of 1676 proposals for sponsored serials were received by Doordarshan. All these proposals were considered and the decision was communicated to the concerned parties. Hence, as on date no proposal for serial is pending consideration in Doordarshan. However, in case of the rejected serials, Doordarshan has been receiving a number of representations for reconsideration. These requests are placed before a Review Committee. Since the process of review is still continuing, it is not possible to say at this stage exactly how many serials would be finally approved.

The cases for review are being dealt with promptly by holding the meetings of the Screening Committee expeditiously.

कच्चे दूध का उत्पादन

2099. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुग्ध उद्योग के विकास में दूध एकत्रित करने का काम तो बढ़ा है किन्तु कच्चे दूध का उत्पादन बढ़ाने की योजना में अभी तक कोई गुणात्मक सफलता प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न तो गांवों में अच्छी नस्ल की 10 प्रतिशत भी गायें उपलब्ध कराई गई हैं और न ही नस्ल सुधार का कोई कार्य चल रहा है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में उन स्थानों के नाम क्या है, जहां नस्ल सुधार का कार्य चल रहा है और इस संबंध में क्या स्थिति है ; और

(घ) हर साल अच्छी नस्ल की कितनी गायें और भैंसें काटी जा रही

हैं ; और कितनी मात्रा में मांस और चमड़े का निर्यात किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1986–87 में दुग्ध उत्पादन 440 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच जाने की आशा है जबकि 1982–83 में यह उत्पादन 358 लाख मीटरी टन था।

(ख) और (ग) गो-पशुओं तथा भैंसों की नस्लों में सुधार लाने का काम राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के लिये इसकी उपयुक्तता के अनुसार शुरू किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने (1) सूरतगढ़ (राजस्थान) (2) चिपलीमा (उड़ीसा), (3) सेमिलिगुडा (उड़ीसा) (4) अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश) (5) हेस्सरघट्टा (कर्नाटक) (6) घामरोड (गुजरात) तथा (7) आवाड़ी (तमिलनाडु) में सात गोपशु प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं ?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नस्ल सुधारने से संबंधित कार्य निम्नलिखित स्थानों पर किया जा रहा है :—

(1) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा।

(2) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश।

(3) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; हरियाणा।

(4) महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, राहुडी, महाराष्ट्र।

(5) जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश।

(6) आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, लाम (आन्ध्र प्रदेश)।

(घ) राज्य पशु संरक्षण अधिनियमों के अनुसार जो भैंसें प्रजनन, दुग्ध उत्पादन या भार ढोने के प्रयोजन के लिये उपयोगी हों, उनके वध की अनुमति नहीं दी जाती है। जो गायें प्रजनन, दुग्ध उत्पादन या अन्य किसी कृषि उपयोग के लिये ठीक हों, उनके वध पर भी प्रतिबन्ध है। गो-मांस के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध है। वर्ष 1984-85 में "मांस-और मांस उत्पादन" तथा "चमड़े" के निर्यात की मात्रायें क्रमशः 51,903 तथा 29,046 मीटरी टन थी।

IRDP assistance to Rajasthan

2100. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what Central assistance has been given to Rajasthan under the Integrated Rural Development Programme during the last three years; and

(b) what are the details regarding the utilisation of this assistance?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) and (b) Central assistance given to Rajasthan under Integrated Rural Development Programme and utilisation during the last three years is as under:—

Year	Central Assistance Given (Rs. in lakhs)	Utilisation including State Share (Rs. in lakhs)
1984-85 . . .	974.00	2052.49
1985-86 . . .	868.91	1934.79
1986-87 . . .	1185.63	2435.50

Allocation for sanitation in Rajasthan

2101. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the financial allocation made for Rajasthan for construction of public sanitation facilities during the last three years;